

## न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठारीन अधिकारी- श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 112/2023

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रड़माराम पुत्र सकाराम जाति मेगवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी	1. नीम्वाराम पुत्र सकाराम 2. रामूदेवी पत्नी सकाराम जाति मेगवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी
--	---

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 3 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक- 19.03.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थीगण वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा गादेसरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 118/2 रकबा 1.3996 हैक्टेयर, खसरा संख्या 39/6 रकबा 2.9933 हैक्टेयर, खसरा संख्या 67/4 रकबा 0.2427 हैक्टेयर कुल रकबा 4.6356 हैक्टेयर का अवस्थित है, जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 मुतवफी सकाराम के विधिक उत्तराधिकारी है सकाराम के दो पुत्र वादी रड़माराम व प्रतिवादी संख्या 1 नीम्वाराम व पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 रामूदेवी है जिसका इस आराजी में बहिस्सा बराबर 1/3 = 1/3 हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड में पक्षकरान के हिस्से खुले हुये है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में खाता अभी संयुक्त है तथा उपरोक्त हिस्सो के अनुसार हम पक्षकार मौके पर काबिज हैं। लेकिन मौके पर किसी प्रकार की माठ बनी हुई नहीं है तथा कानूनी बंटवारा किया हुआ नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की खातेदारी मे हस्तक्षेप करते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो वादी के सगा भाई व माता है, जिसने वादी की बिना सहमति से बिना बंटवाड़ा

करवाये भूमि का बैचान कर दिया गया है। उक्त बैचान के आधार पर वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन में हस्तक्षेप कर रहे है। वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने का अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है। वादग्रस्त आराजी का ख्याता अभी संयुक्त है कोई भी सहखातेदार बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये विशिष्ट भू भाग का बैचान नहीं कर सकता है। इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनके किसी अनजानी व्यक्ति को भूमि बैचान करने का अधिकार नहीं है। कानूनन यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा को बैचान करना चाहता है तो सर्वप्रथम कर, खरीद करने का अधिकारी वादी है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज है और सभी का काश्त व कब्जा संयुक्त चला आ रहा है मगर वर्तमान समय में भूमि के भावों में बढ़ोतरी होने के कारण विप्रार्थीगण बिना अपना हिस्सा तय करवाये व बिना बंटवारा करवाये बैचान करने पर उतारू है व प्रार्थी को भी विप्रार्थीगण द्वारा धमकी दी कि तुम अपना हिस्सा हिस्सा हम जिसे बैचान कर रहे है उन्हे बैचान कर दो अन्यथा हम लोग हमारे हिसाब से बैचान कर लेंगे। अगर उनके द्वारा बिना घोषणा व बिना बंटवारा के बैचान कर दिया गया तब अनजान कंता वादग्रस्त आराजी में अद्वि किस्म की व प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज हो जावेगा व अनजान कंता के मध्य विवाद भी उत्पन्न होगा। इस कारण विप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विप्रार्थीगण बिना बंटवारा के किसी भी अनजान कंता को वादग्रस्त आराजी का बैचान नहीं करे व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थी के वकील के तथ्यों के पर विप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस के दौरान प्रार्थी के तथ्यों पर स्वीकारोक्ति देते हुए तर्क दिया है कि पक्षकारान के मध्य वाहमी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है, परन्तु पक्षकारान के मध्य विधिवत रेकर्डेड बंटवाड़ा नहीं किया हुआ है, ऐसी स्थिति यदि अदालत उचित समझे, तो विधिवत बंटवाड़ा नहीं हो तब तक कब्जे काश्त के अनुरूप काबिज पक्षकारान की भूमि पर किसी पक्ष द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने हेतु दोनों पक्षों को पाबन्द किया जा सकता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा मुतवफी सकाराम के पुत्र-पत्नि है। जहां तक विवादित भूमि संयुक्त सामलाती कब्जे काश्त की होने से उसके बैचान इत्यादि से मौके पर कब्जे काश्त को लेकर नया विवाद उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्वीकार किया कि "यदि अदालत उचित समझे, तो विधिवत बंटवाड़ा नहीं हो तब तक कब्जे काश्त के अनुरूप काबिज पक्षकारान की भूमि पर किसी पक्ष द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने हेतु दोनों पक्षों को पाबन्द किया जा सकता है।" परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से वेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोवदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढ़ती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहीत होने से रथगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को मूलवाद के ताफैसला तक जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा गादेसरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 118/2 रकबा 1.3996 हैक्टेयर, खसरा संख्या 39/6 रकबा 2.9933 हैक्टेयर, खसरा संख्या 67/4 रकबा 0.2427 हैक्टेयर कुल रकबा 4.6356 हैक्टेयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का बेचान अथवा अनाधिकृत अतिक्रमण इत्यादि नहीं कर वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।